

भारत में जाति-आधारित हिंसा की नरिंतरता तथा नहिति चिंताएँ

यह एडिटरियल 25/07/2023 को 'हृदिस्तान टाइम्स' में प्रकाशित [“Caste has no place in a modern democracy”](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत में जाति-आधारित हिंसा की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम 1989](#), [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#), [वन अधिकार अधिनियम 2006](#), [अनुच्छेद 14](#), [पंचायतें](#), [नगर पालिकाएँ](#), [नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955](#); हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतिषिध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013

मेन्स के लिये:

जाति-आधारित हिंसा के कारण और परिणाम

भारत में जाति-आधारित हिंसा **भेदभाव और उत्पीडन का एक रूप** है जो अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) से संबंधित लोगों को लक्षित करती है, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में हाशिए पर स्थिति और वंचित समूह हैं।

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम, 1989](#) जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों और विशेष कानून के बावजूद, जाति-आधारित अपराध विभिन्न रूपों और क्षेत्रों में घटित होते रहते हैं, जो लाखों लोगों के [मौलिक अधिकारों](#) और [मानवाधिकारों](#) का उल्लंघन करते हैं।

भारत में जाति-आधारित अपराध की स्थिति

- **भारत में जाति-आधारित अपराध:**
 - जाति-आधारित अपराधों में शारीरिक हमला, हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीडन, यातना, आगजनी, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण, भूमि पर कब्जा, जबरन वसिस्थापन और अपमान एवं हिंसा के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं।
 - [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो \(NCRB\)](#) द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Crime in India Report) 2019 के अनुसार, वर्ष 2019 में SCs और STs के विरुद्ध अपराधों में क्रमशः 7% और 26% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
 - इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में हर दिन बलात्कार के 88 मामले दर्ज किये जाते हैं। इनमें से कुछ मामले जाति-आधारित अपराधों से संबंधित होते हैं।
- **अपराध दर और आरोप पत्रों में क्षेत्रीय अंतर:**
 - जाति-आधारित अपराध क्षेत्रीय विशेषताओं और उनसे लड़ने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में अंतर से भी प्रभावित होते हैं।
 - उदाहरण के लिये, मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध दर (Crime Rate) सबसे अधिक थी।
 - मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में भी अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध दर सबसे अधिक थी, जबकि वर्ष 2019 में यह राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर था।
 - लेकिन आँकड़ों से यह भी पता चला कि मध्य प्रदेश में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने की दर अधिकांश भारतीय राज्यों की तुलना में सबसे अधिक थी।
 - इसका पड़ोसी राज्य राजस्थान इस मामले में काफी पीछे था, जिससे प्रकट होता है कि राज्य पुलिस को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।

भारत में जाति-आधारित अपराधों के कारण

- **जाति व्यवस्था और पदानुक्रमित संरचना:**
 - जाति व्यवस्था—जो वंश और व्यवसाय पर आधारित एक प्राचीन सामाजिक स्तरीकरण है, एक कठोर पदानुक्रमित संरचना का निर्माण करता है जहाँ व्यक्तियों को विशेषित जातियों में वर्गीकृत किया जाता है।

- यह व्यवस्था कथित उच्च जातियों में श्रेष्ठता की भावना और नचिली जातियों में हीनता की भावना को बढ़ावा देती है, जिससे नचिली जातियों के वरिद्ध भेदभाव और हिसा को बढ़ावा मलित है।
- सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मान्यताएँ:
 - सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मान्यताएँ, जो प्रायः पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जाति-आधारित श्रेष्ठता और हीनता की धारणा को पुष्ट करती हैं।
 - ये मानदंड भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और प्रथाओं का सामान्यीकरण करते हैं, जिससे जाति-आधारित हिसा से मुक्तिपाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- आर्थिक शोषण:
 - जाति-आधारित हिसा कभी-कभी आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित होती है। नचिली जातियों के व्यक्तियों को प्रभुत्वशाली जाति समूहों के हाथों शोषण, बलात् श्रम और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ सकता है, जिससे संघर्ष और हिसा की स्थिति बिन सकती है।
- राजनीतिक सत्ता संघर्ष:
 - जाति-आधारित हिसा राजनीतिक सत्ता संघर्ष से भी जुड़ी हुई है। प्रभुत्वशाली जाति समूह अपना प्रभुत्व और प्रभाव बनाए रखने के लिये नचिली जातियों के व्यक्तियों की राजनीतिक आकांक्षाओं और प्रतिनिधित्व का दमन करने के लिये हिसा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अंतरजातीय विवाह:
 - पारंपरिक जाति सीमाओं को चुनौती देने वाले अंतरजातीय विवाहों को कभी-कभी अपनी जाति की शुद्धता की रक्षा के नाम पर समाज के रूढ़िवादी वर्गों की ओर से शत्रुता और हिसा का सामना करना पड़ता है।
- कानूनों के कार्यान्वयन का अभाव:
 - कानूनी सुरक्षाओं के बावजूद, जाति-आधारित हिसा के वरिद्ध कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन कुछ भूभागों में चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिससे अपराधियों के लिये दंडमुक्ति की एक संस्कृति (culture of impunity) का निर्माण होता है।

जाति-आधारित अपराधों के प्रभाव

- मानवाधिकारों का उल्लंघन:
 - जाति-आधारित हिसा **जीवन, गरमा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों सहित मानवाधिकारों** के गंभीर उल्लंघन का कारण बनती है।
 - ऐसी हिसा के शिकार लोग शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति उठाते हैं, जिससे उनके लयिसदमा और दीर्घकालिक भावनात्मक संकट की स्थिति बिनती है।
- सामाजिक वखिडन:
 - जाति-आधारित हिसा सामाजिक वभिजन को गहरा करती है और वभिनिन जाति समूहों के बीच शत्रुता पैदा करती है।
 - यह सामाजिक एकता को बाधति करती है और एक सामंजस्यपूर्ण एवं समावेशी समाज के निर्माण के प्रयासों को कमजोर करती है।
- भय और असुरक्षा:
 - जाति-आधारित हिसा हाशिए पर स्थिति समुदायों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती है।
 - हिसा और भेदभाव का भय 'सेलफ-सेंसरशिप' को जन्म दे सकता है और प्रभावित व्यक्तियों की अभिव्यक्ति एवं अबाध संचरण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है।
- विकास और सशक्तीकरण में बाधाएँ:
 - जाति-आधारित हिसा हाशिए पर स्थिति समुदायों के विकास और सशक्तीकरण को बाधति करती है।
 - यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुँच को सीमति करती है, उन्हें अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकने से अवरुद्ध करती है।
- संस्थानों के प्रति विश्वास की हानि:
 - जाति-आधारित हिसा राज्य के संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय प्रणाली के प्रति भरोसे का क्षरण करती है। पीड़ित और संबंधित समुदाय आगे और उत्पीड़न के भय से या तंत्र पर भरोसे की कमी के कारण न्याय की मांग करने या घटनाओं की रिपोर्टिंग में झिझक रख सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय छवि:
 - जाति-आधारित हिसा की मौजूदगी एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
 - यह वैश्विक समुदाय के बीच जातिगत पहचान के आधार पर भेदभाव और हिसा की व्यापकता के बारे में चर्चा पैदा करता है।

जाति आधारित भेदभाव के वरिद्ध कौन-से सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:
 - **अनुच्छेद 15:** राज्य किसी नागरिक के वरिद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई वभिद नहीं करेगा।
 - **अनुच्छेद 16:** राज्य के अधीन किसी नयोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, नवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे वभिद किया जाएगा।
 - **अनुच्छेद 335:** संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियों करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।
 - **अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332:** लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सीटों का आरक्षण।
- संवैधानिक निकाय:
 -

- [राष्ट्रीय अनुसूचति जात आयोग](#) (National Commission for Scheduled Castes)
- [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग](#) (National Commission for Scheduled Tribes)
- सांविधिक प्रावधान:
 - [अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात \(अत्याचार नविवरण\) संशोधन अधिनियम, 2018](#)

भारत में जात-आधारित अपराधों को रोकने और इसके नविवरण के संभावित समाधान

- कानूनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना:
 - अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात अधिनियम 1989; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955; हाथ से मैला उताने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतिषेध और उनका पुनरवास अधिनियम 2013 ।
- राज्य संस्थानों को सशक्त करना:
 - अपराधियों को रोकने, उनकी जाँच करने, मुकदमा चलाने, दंडित करने और पुनरवास के लिये पुलिस, न्यायपालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र को सशक्त करना होगा ।
- जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना:
 - उच्च जातियों, नचिली जातियों, नागरिक समाज संगठन, मीडिया, शिक्षा जगत, धार्मिक नेता और राजनीतिक दल जैसे सभी हतिधारकों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना होगा ।
- अनुसूचति जात/जनजात को सशक्त बनाना:
 - शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक लामबंदी, कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं के माध्यम से अनुसूचति जात/जनजात को सशक्त बनाना होगा ।
- संवाद और मेल-मिलाप को बढ़ावा देना:
 - विश्वास एवं एकजुटता का निर्माण, रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रहों को चुनौती देना और विविधता एवं मानवीय गरमा के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना एक सार्थक पहल होगी ।

अभ्यास प्रश्न: जात-आधारित हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो पीड़ितों के संवैधानिक अधिकारों और मानवीय गरमा का उल्लंघन करती है । भारत में जात-आधारित हिंसा के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिये ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न 1. बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जात की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित वसितृत उत्तर दीजिये । (2020)

प्रश्न 2. “जात व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है । अतः भारत में जात व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है । टपिपणी कीजिये । (2018)